



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]

No. 1479]

नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

(आयकर)

का.आ. 1782(अ).—चूंकि करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और गुरुर्नसे राज्य के बीच लंदन में 20 दिसम्बर, 2011 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है)।

और चूंकि, उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 11 जून, 2012 है, जो कि करार के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अंधिसूचना की तारीख है।

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि भारत गणराज्य की सरकार और गुरुर्नसे राज्य के बीच करों के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इसके साथ संलग्न उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 11 जून, 2013, जो उपर्युक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख है, से लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 30/2012/फा. सं. 503/1/2009-एफटीडी-I]

सजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्टेट आफ गुर्जर्नसे

के बीच करार

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और स्टेट आफ गुर्जर्नसे (संविदाकारी पक्ष), करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को अधिशासित करने वाली निबंधनों एवं शर्तों को सुगम एवं सुकर बनाने का इच्छुक है,

जबकि यह स्वीकृत है कि स्टेट आफ गुर्जर्नसे को युनाइटेड किंगडम से सुपुर्दगी की शर्तों के अंतर्गत स्टेट आफ गुर्जर्नसे से वार्ता करने, निष्पत्ति करने, निष्पादन करने तथा इस करार की शर्तों के अध्यधीन भारत गणराज्य की सरकार के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार को समाप्त करने का अधिकार है;

अतः, अब संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित करार को, जिसमें केवल संविदाकारी पक्षों की ओर से बाध्यताएं शामिल हैं, निष्पत्ति करने के लिए सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद 1 करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत है। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहाँ तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद 2**क्षेत्राधिकार**

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार किया जाएगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और उन ही उन व्यक्तियों के पास अथवा उनके द्वारा प्राप्त है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3**सम्मिलित कर**

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :

- क) भारत में, केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं;
- ख) गुर्जरनसे में, परामर्शी राज्य द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार और विवरण के कर।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4**परिभाषाएं**

इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :

- क) भारत से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं।
- ख) गुर्जरनसे से तात्पर्य गुर्जरनसे, एल्डने और हेम से है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उन द्वीपसमूहों के निकटवर्ती समुद्री भू-क्षेत्र शामिल हैं।

ग) सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो ;

घ) कम्पनी से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है ;

ड.) सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य -

- (i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ;
- (ii) गुर्वन्से के मामले में, आयकर निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि ;

घ) आषाधिक कर मामलों का तात्पर्य इस करार के लागू होने से पहले अथवा बाद में उन कर मामलों से है जिसमें अभिप्रेत संव्यवहार शामिल है, जिस पर आषाधिक कानूनों अथवा अनुरोधकर्ता पक्ष के इस करार द्वारा शामिल किए गए करों से संबंधित कानूनों के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है ;

छ) सूचना से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो ;

ज) सूचना एकत्र करने वाले उपाय से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं ;

झ) व्यक्ति में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;

ज) शेयरों का प्रमुख वर्ग से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है ;

ट) सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है । निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हो ;

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

३) सांवजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेज पर सूचीबद्ध है वशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हो;

४) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेज से तात्पर्य है -

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेज, बम्बई स्टॉक एक्सचेज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेज;

(ii) गुर्जरसे म, चैनल आइलैण्ड स्टॉक एक्सचेज और;

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों।

५) अनुरोधित पक्ष से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है;

६) अनुरोध करने वाले पक्ष से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है;

७) कर से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद -12 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस संविदाकारी पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस रहता है।

अनुच्छेद 5 अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का

विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर्त-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता है। अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी केवल इस अनुच्छेद के अनुपालन में सूचना हेतु अनुरोध करेगा, जब अनुरोधित सूचना को दूसरे उपायों से प्राप्त करना अक्षम हो, सिवाय उसके, जहां ऐसे उपायों का सहारा अनुपातहीन मुश्किल बढ़ाता हो।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह अनुरोधित पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

- क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना;
- ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, आन्सटालटन और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व शृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना;
- ग) सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना; और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न किए बिना प्राप्त की जा सकती हो ।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

- क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान ;
- ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है ;
- ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा ;
- घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है ;
- ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण अथवा उसके द्वारा प्राप्त है ,
- च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने अथवा प्राप्त करने का अनुमान है और
- छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा यह इस कार के अनुरूप है ; और

यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे ।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध को स्वीर करेगा और अपने बेहतर प्रायासों से शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के कम से कम 14 दिन पहले किए गए अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए मनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले अनुरोधित पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निन्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :

वर्ग, जहां अनुरोध इस करार के अनुसर नहीं किया गया हो, अथवा

ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी ; अथवा

ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :

क) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है ; अथवा

ख) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो कानूनी विशेषाधिकार के तहत हो, जैसा कि संगत संविदाकारी पक्ष के घरेलू कानून के तहत व्यवस्था की गई है ; अथवा

ग) प्रशासनिक उपाय करना जो इसके कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर हो, बशर्ते कि इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं पर कोई प्रभाव डालेगा ।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर भना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है ।

4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने स्वयं के कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने स्वयं के कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असर्वाधिक होगा ।

5. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध आवेदन पक्ष द्वारा आवेदन पक्ष के कर कानून के ऐसे उपर्युक्त को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो

अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रिक अथवा नागरिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में आवेदक पक्ष के एक राष्ट्रिक अथवा नागरिक की तुलना में पक्षपात करता है।

अनुच्छेद 8 विधान का कार्यान्वयन

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और उसे प्रवर्तित करने के लिए किसी आवश्यक विधान को अधिनियमित करेंगे।

अनुच्छेद 9 गोपनीयता

1. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई और प्राप्त की गई समस्त सूचना को गोपनीय रखा जाएगा।
2. ऐसी सूचना को अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से संबंधित केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा और इसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा जिसमें किसी अपील का निर्धारण शामिल है। इन प्रयोजनों के लिए सूचना को लोक अदालत कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट किया जा सकता है।
3. ऐसी सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की लिखित सहमति के बाहर अनुच्छेद 1 में बताए गए प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।
4. इस करार के तहत अनुरोधकर्ता पक्ष को उपलब्ध कराई गई सूचना को किसी अन्य न्याय-निर्णयन में प्रकट नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 10 लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हो, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यधीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, (जिसमें मुकदमेवाजी के संबंध में बाहरी सलाहकारों की नियुक्ति की लागतें अथवा अन्यथा, अनुरोध को पूरा करने में आवश्यक लागतें शामिल हैं) यदि वे 500 अमेरिकी डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।
2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 अमेरिकी डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-

दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को बहन करेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर पश्चात्याश करेंगे।

अनुच्छेद 11 भाषा

सहायता हेतु अनुरोध और उनसे संबंधित प्रत्युत्तरों को अंग्रेजी में लैभार किया जाएगा।

अनुच्छेद 12 पारस्परिक करार विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयारा करेंगे। इसपें अतिरिक्त संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5, 6 और 10 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।

2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 13 प्रोतोकोल

संबद्ध प्रोतोकोल इस करार का अभिन्न अंग होगा।

अनुच्छेद 14 प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और निम्न पर तुरंत प्रभाव होगा -

- (क) उस तारीख को आपराधिक कर मामलों के संबंध में ; और
- (ख) उस तारीख को अनुच्छेद 1 में शामिल सभी मामलों के संबंध में, परंतु उस तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली कराधेद अवधियों के लिए अथवा जहां कोई कराधेय अवधि नहीं है, वहां उस तारीख को अथवा उसके बाद उद्भूत सभी कर प्रभारों के लिए।

अनुच्छेद 15

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्षों के समाप्त होने के बाद समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है।
3. इस तरह वां समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
4. इस करार के समाप्त होने की स्थिति में, ऐसे समापन के होते हुए भी दोनों संविदाकारी पक्ष करार के अंतर्गत प्राप्त की गई किसी भी सूचना के संबंध में अनुच्छेद 9 के उपबंधों के तहत बाध्य होंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

मैं वर्ष दो हजार ख्यारह के दिसंबर माह के बीसवें दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

स्टेट आफ गुर्नर्से
की ओर से

राजेश एन. प्रसाद

(राजेश एन. प्रसाद)
युनाइटेड किंगडम में भारत के
कार्यकारी उच्चायुक्त

Henry Tracy

(डिप्टी लिंडन एस ट्रैट)
मुख्यमंत्री, गुर्नर्से

प्रोतोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और स्टेट आफ गुर्नर्से (संविदाकारी पक्ष) निम्नलिखित उपबंधों पर, जो इस करार के अभिन्न अंग के रूप में होंगे, पर करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान हेतु, दोनों सरकारों के बीच करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं :

- 1) सक्षम प्राधिकारी करार के उन उपबंधों की व्याख्या करते समय जो उस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) आदर्श करार में उपबंधों के समान हैं, आर्थिक सहयोग एवं विकास संबंधी संगठन के कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार, 2002 से संबंधित टीका-टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे।
- 2) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 7 के प्रयोजनार्थ, यह समझा जाता है कि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी :-

 - (क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध की प्राप्ति की पुष्टि करेंगे और अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में विसंगतियाँ, यदि कोई हों, से अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेंगे;
 - (ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त करते और प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को पेश करने में आई बाधाएं शामिल हों अथवा सूचना प्रस्तुत करने से मना करे, तो वह अपनी असमर्थता के कारणों, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी मनाही के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को तत्काल सूचित करेगा।

- 3) करार के अनुच्छेद 10 में असाधारण लागत पद की निम्नानुसार व्याख्या की जाएगी :

 - (क) असाधारण लागत के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं, परन्तु उस ताक सीमित नहीं है :

 - (i) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को दस्तावेजों अथवा रिकॉर्डों को पुनः प्रस्तुत करने और भेजने की उचित लागतें;

- (ii) रिकॉर्ड के प्रतिलिपिकरण और सूचना के लिए विशिष्ट अनुरोध से संबंधित अनुसंधान हेतु वित्तीय संस्थान अथवा अन्य तीसरे पक्ष के रिकॉर्ड कीपर द्वारा लगाए गए उचित शुल्क ;
- (iii) साक्षात्कारों, बयानों अथवा घोषणाओं के आशुलिपिक्रिय रिपोर्टों के लिए उचित लागते
- (iv) अनुप्रोज्य कानून के तहत स्वीकृत राशियों के अनुसार निर्धारित उस व्यक्ति की उचित फीस और खर्च, जो विशेष सूचना अनुरोध से संबंधित साक्षात्कार, साक्ष्य अथवा गवाही हेतु भारत अथवा गुरुनसे में स्वेच्छा से आएँ ; और
- (v) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से नियुक्त अथवा प्रतिधारित गैर सरकारी वकील के लिए सूचना हेतु विशिष्ट अनुरोध से संबंधित अनुरोधित पक्ष के न्यायालयों में मुकदमा लड़ने के लिए उचित कानूनी फीस ;

ख) असाधारण लागत में अनुरोधित पक्ष द्वारा तथा अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों के प्रत्युत्तर में एवं उनकी पुनरीक्षा करने में उपगत साधारण प्रशासनिक और ऊपरी खर्च शामिल नहीं हैं।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

राजेश नाथ

(राजेश एन. प्रसाद)
युनाइटेड किंगडम में भारत के
कार्यकारी उच्चायुक्त

स्टेट आफ गुरुनसे
की ओर से

John Tress

(डिप्टी लिंडन एस ट्रॉट)
मुख्यमंत्री, गुरुनसे

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

(INCOME-TAX)

S.O. 1782(E).—Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the States of Guernsey for the exchange of information with respect to taxes was signed at London on the 20th day of December, 2011 (hereinafter referred to as the said Agreement)

And whereas, the date of entry into force of the said Agreement is the 11th day of June, 2012, being the date of the later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of article 14 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the Agreement between the Government of the Republic of India and the States of Guernsey for the exchange of information with respect to taxes, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 11th June, 2012, that is ,the date of entry into force of the said Agreement.

[Notification No. 30/2012/F. No. 503/I/2009-FTD-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE STATES OF GUERNSEY
FOR
THE EXCHANGE OF INFORMATION
WITH RESPECT TO TAXES**

Whereas the Government of the Republic of India and the States of Guernsey (the "Contracting Parties"), desiring to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information with respect to taxes;

Whereas it is acknowledged that the States of Guernsey has the right under the terms of its Entrustment from the UK to negotiate, conclude, perform and subject to the terms of this Agreement terminate a tax information exchange agreement with the Government of the Republic of India;

Now, therefore, the Contracting Parties have agreed to conclude the following Agreement, which contains obligations on the part of the Contracting Parties only.

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The Contracting Parties, through their competent authorities, shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

Information shall be exchanged in accordance with this Agreement without regard to whether the person to whom the information relates is, or whether the information is held by, a resident of a Contracting Party. However, a requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor is in the possession of, or in the control of, or obtainable by, persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

- a) in India, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or the Governments of political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied;
- b) in Guernsey, taxes of every kind and description imposed by the States of Deliberation.

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures which may affect the obligations of that Contracting Party pursuant to this Agreement.

Article 4 Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

- a) "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with International law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
- b) "Guernsey" means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those Islands in accordance with international law;
- c) "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;
- d) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- e) "competent authority" means
 - (i) in the case of India, the Finance Minister, Government of India, or its authorized representative;
 - (ii) in the case of Guernsey, the Director of Income Tax or his delegate;
- f) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws or the laws relating to taxes covered by this Agreement of the requesting Party;
- g) "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;
- h) "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a requested Party to obtain and provide the requested information;

- i) "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;
- j) "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- k) "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- l) "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- m) "recognised stock exchange" means
 - (i) in India, the National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange, and any other stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India;
 - (ii) in Guernsey, the Channel Islands Stock Exchange; and
 - (iii) any other stock exchange which the competent authorities agree to recognise for the purposes of this Agreement;
- n) "requested Party" means the Contracting Party which is requested to provide information, or which has provided information;
- o) "requesting Party" means the Contracting Party submitting a request for information to, or having received information from, the requested Party;
- p) "tax" means any tax to which this Agreement applies.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 12 of this

Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Contracting Party, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
4. Each Contracting Party shall ensure that it has the authority, in accordance with the terms of this agreement, to obtain and provide, through its competent authority, upon request:
 - a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
 - b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons,

Including within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain;

c) In the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; in the case of trusts, information on settlers, trustees and beneficiaries; In the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and equivalent information in the case of entities that are neither trusts nor foundations.

5. This Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- a) the identity of the person under examination or investigation;
- b) the period for which the information is requested;
- c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;
- d) the tax purpose for which the information is sought;
- e) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession of, or is in the control of, or obtainable by, a person within the jurisdiction of the requested Party;
- f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or in control of or able to obtain the requested information;
- g) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party, then the competent authority of the

requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

- h a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavors to forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, made at least 14 days in advance, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested Party, in which case the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 7**Possibility of Declining a Request for Information**

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
 - a) where the request is not made in conformity with this Agreement; or
 - b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 - c) where disclosure of the information would be contrary to public policy (*ordre public*) of the requested Party.
2. This Agreement shall not impose on a requested Party the obligation:
 - a) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph; or
 - b) to obtain or provide information subject to legal privilege as provided for under the domestic law of the relevant Contracting Party; or
 - c) to carry out administrative measures at variance with its laws and administrative practices, provided nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under paragraph 4 of Article 5.
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain in similar circumstances under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request from the requested Party under this Agreement.

5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.

Article 8

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

Article 9

Confidentiality

1. All information provided and received by the competent authorities of the Contracting Parties shall be kept confidential.
2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.
3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested Party.
4. Information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

Article 10

Costs

1. Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and, subject to the provisions of this Article, extraordinary costs incurred in providing assistance (including

costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise necessary to comply with the request) shall, if they exceed \$ US 500, be borne by the requesting Party.

2. The competent authorities will consult each other, in advance, in any particular case where extraordinary costs are likely to exceed \$ US 500 to determine whether the requesting Party will continue to pursue the request and bear the cost.
3. The competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article.

Article 11

Language

Requests for assistance and responses thereto shall be drawn up in English.

Article 12

Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 10 of this Agreement.
2. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for the purposes of reaching agreement under this Article.

Article 13

Protocol

The attached Protocol shall be an integral part of this Agreement.

Article 14

Entry into Force

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing of the completion of their procedures for entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and shall thereupon have effect forthwith:
 - a) for criminal tax matters on that date; and

b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 15 Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Contracting Party.
2. Either Contracting Party may, after the expiry of two years from the date of its entry into force, terminate this Agreement by serving a written notice of termination to the other Contracting Party through appropriate channels.
3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the provisions of the Agreement.
4. If the Agreement is terminated the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 9 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at London on this Twentieth day of December, 2011, each in the Hindi, and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India :

Rajesh N. Prasad
Acting High Commissioner of India
to the United Kingdom

For the States of
Guernsey :

Deputy Lyndon S. Trott
Chief Minister of
Guernsey

Protocol :

The Government of the Republic of India and the States of Guernsey (the "Contracting Parties") have agreed at the signing of the Agreement between the two Governments for the Exchange of Information with respect to Taxes on the following provisions which shall form an integral part of the said Agreement:

- 1) The competent authorities may take into consideration the commentaries pertaining to the 2002 Agreement on Exchange of Information on Tax Matters of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD Model Agreement) when interpreting provisions of the Agreement that are identical to the provisions in that OECD Model Agreement.
- 2) For the purpose of paragraph 7 of Article 5, it is understood that the competent authority of the requested Party shall:
 - a) confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request;
 - b) if the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.
- 3) The term "extraordinary costs" in Article 10 of the agreement shall be interpreted as follows:
 - a) Examples of "extraordinary costs" include, but are not limited to, the following:
 - (i) reasonable costs of reproducing and transporting documents or records to the Competent Authority of the requesting Party;
 - (ii) reasonable fees imposed by a financial institution or other third party record keeper for copying records

and research related to a specific request for information;

- (iii) reasonable costs for stenographic reports of interviews, depositions or testimony;
- (iv) reasonable fees and expenses, determined in accordance with amounts allowed under applicable law, of a person who voluntarily appears in India or Guernsey for an interview, deposition or testimony relating to a particular information request; and
- (v) reasonable legal fees for non-government counsel appointed or retained with approval of the Competent Authority of the requesting Party, for litigation in the courts of the requested Party related to a specific request for information;

b) "extraordinary costs" do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the requesting Party.

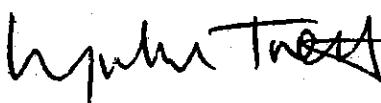
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at London on this Twentieth day of December, 2011, each in the Hindi, and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India :


Rajesh N. Prasad
Acting High Commissioner of India
to the United Kingdom

For the States of
Guernsey :


Deputy Lyndon S Trott
Chief Minister of
Guernsey